राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023

राजस्थान सरकार द्वारा पेश किये गए **राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023** का उद्देश्य राज्य में लोगों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना है। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को मुद्रास्फीति से निपटने **और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार करने** में मदद करना है।

- विधेयक में तीन व्यापक श्रेणियाँ हैं: **न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोज़गार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार।**

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023:

- **विधेयक के प्रमुख घटक:**
  - **न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार:**
    - यह विधेयक प्रत्येक **वयस्क नागरिक को वर्ष में 125 दिन** न्यूनतम आय की गारंटी देता है।
    - प्रत्येक वयस्क नागरिक को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम **(MGNREGA)** के माध्यम से न्यूनतम आय प्राप्त होगी।
      - राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मनरेगा के 1**00 दिनों में अतिरिक्त 25 दिन का और रोज़गार सुनिश्चित करेगा।**
  - **गारंटीकृत रोज़गार का अधिकार:**
    - शहरी और ग्रामीण रोज़गार योजनाओं में कार्य पूरा होने के बाद सरकार **साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान करेगी।**
    - एक नामित **अधिकारी** यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल, पंजीकृत जॉब कार्ड पते के **पाँच किलोमीटर** के अंतर्गत हों।
    - यदि **आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोज़गार प्रदान नहीं किया जाता है,** तो आवेदक को **साप्ताहिक बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा** 'परंतु किसी भी मामले में यह अवधि एक पखवाड़े से अधिक नहीं होगी'।
  - **गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार:.**
    - विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि **वृद्धावस्था, विशेष रूप से विकलांग, विधवा और एकल महिलाओं** जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को पेंशन मिले।
      - **वित्तीय वर्ष 2024-2025 से पेंशन में दो किश्तों में 15% की वार्षिक वृद्धि की** जाएगी।
- **नकद हस्तांतरण योजनाओं में अंतर:**
  - राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक अद्वितीय है क्योंकि यह कानूनी रूप से न्यूनतम **आय सहायता और गारंटीकृत रोज़गार एवं पेंशन** दोनों सुनिश्चित करता है, जो इसे नियमित **नकद हस्तांतरण योजनाओं** से अलग करता है। यह महात्मा गांधी के व्यापक कल्याणकारी उपायों के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
  - यह विधेयक **राज्य के सभी परिवारों को कवर** करता है। इसके साथ विभिन्न कमज़ोर समूहों को रोज़गार और पेंशन सहायता प्रदान करता है। इस विधेयक के कारण **नकद हस्तांतरण योजनाओं का कवरेज सीमित** हो सकता है।
  - इस विधेयक में **पेंशन में वार्षिक वृद्धि** करना शामिल है यह सुनिश्चित करते हुए कि वे **मुद्रास्फीति के साथ तालमेल** बनाए रखा जाए। नकद हस्तांतरण योजनाओं में इस प्रकार के प्रावधान नहीं हो सकते हैं।
  - यह विधेयक सामाजिक सुरक्षा के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है जिसका लक्ष्य समाज के कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुँचाना है।
- **विधेयक की आलोचना:**
  - विधेयक को आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों के लिये प्रशंसा मिली है जबकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि **प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य के वित्त पर दबाव डाल सकता है।**
  - आलोचक योजना की **दीर्घकालिक स्थिरता** और करदाताओं पर पड़ने वाले संभावित बोझ के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।

INDIA'S TRYST WITH INCOME SUPPORT

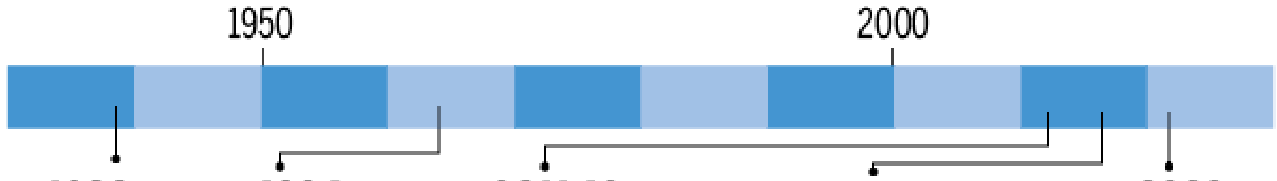

1938
A minimum income standard discussed

1964
Plan to start such a programme was on the horizon

2011-12
2 pilot projects conducted in 8 villages of Madhya Pradesh

2016-17
Economic Survey suggests scheme for bottom 75% of population, while rolling back some subsidies

2022
Sikkim Democratic Front plans to roll out UBI

UBI ACROSS THE WORLD

US | Alaska Permanent Fund distributes part of the state's oil revenues to all residents on per-capita basis

Stockton, California
Secured funding from private non-profits to launch a small project with about 100 participants receiving $500 a month for about 18 months

Finland | Scheme started in 2017 to pay 2,000 jobless people assistance of €560 a month stopped last year

Kenya | Largest experiment underway with some villages receiving $0.50-1 a day

Brazil | Has run experiments

Canada | Ontario plans to test a basic income scheme

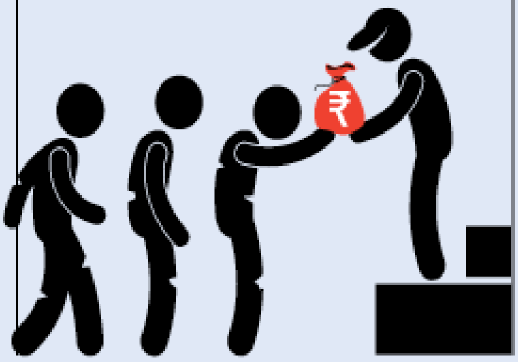

France | A senate committee has recommended an experiment

UK & Germany | Studies have been conducted

Scotland | Committed funds to conduct an experiment

Barcelona, British Columbia | Plans to start experiments

Switzerland | Plan to give everyone right to basic income defeated in 2016

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-minimum-guaranteed-income-bill,-2023